का अनुमोदन किया है जिसमें यह तीनों क्षेत्र भी शामिल हैं।

कपास के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य

2044. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाली कपास और उसके उत्पादों का मूल्य लगभग 7,100 करोड़ रुपये होता है :

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कपास के विकास और कपास को प्रसंस्कृत करके उत्पादित की जाने वाली अन्य वस्तुओं के विकास एवं विस्तार हेतु किये जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्य पर केवल 6 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि देश में वस्त्र उद्योग के विकास और विस्तार हेतु पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वापरि बनाने हेतु नए अन्वेषणों के आधार पर कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 में उत्पादित गैर-ओटाई वाली कपास का मूल्य लगभग 6,600 करोड़ रु० होगा। मूल्य के रूप में सूती यार्न तथा सूती कपड़े के उत्पादन क्रमश : लगभग 10009 करोड़ रु० तथा 45,316 करोड़ रु० होगा।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान कपास की वृद्धि के लिए हुए अनुसंधान तथा विकास कार्य पर 595.937 लाख रु० मूल्य की राशि खर्च की गई। वर्ष 1992-93 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूती वस्त्र अनुसंधान संघ को 373 लाख रु० मूल्य की सहायता प्रदान की गई।

(घ) जी हां।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यार्न और कपड़े दोनों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उदारीकरण उपाय शुरु करने, सरकार की लाइसेंस संबंधी नीति समाप्त करने, ई पी सी जी योजना, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना करने तथा उत्पाद तथा आयात शुल्क में संशोधन करने जैसे नीतिगत हस्ताक्षेप करने से वस्त्र उद्योग का विकास सुनिश्चित हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

2045. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो कुल आवंटित राशि में से कपड़ा मिलों, विद्युतकरघा

और हथकरघा क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा निर्मित कपड़े की न केवल मात्रा अधिक है बल्कि यह कपड़ा मिलों द्वारा निर्मित कपड़े की तुलना में सस्ता भी है और विद्युतकरघा उद्योग अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता है ;

(घ) यदि हां, तो कपड़ा मिलों की अपेक्षा विद्युतकरघा क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन न दिये जाने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले में नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) सरकार वस्त्र उद्योग के सभी तीनों क्षेत्रों के उनके सहज बल को मद्देनजर रखते हुए उनके विकास के प्रति वचनबद्ध है। मिल क्षेत्र और विद्युतकरघा क्षेत्र के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है।

अमरीका में सिले-सिलाए भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हानि

2046. **श्री अजीत जोगी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन द्वारा सिले-सिलाए भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिये जाने के कारण सिले-सिलाए कपड़ों के स्थापित निर्यातकों को भारी घाटा उठाना पड़ा जैसा कि 7 जनवरी, 1993 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीकी प्रशासन द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) अमरीकी सरकार ने अक्तूबर/नवम्बर, 1992 में परिधान की दो श्रेणियों अर्थात् काटन लेडीज ब्लाउजिस एण्ड शर्ट्स (श्रेणी 341) तथा काटन एण्ड मैन मेड फाइबर जैन्ट्स शर्ट्स (श्रेणी 340/640) पर इस आधार पर प्रतिबन्ध लगाया था कि भारत ने इन दोनों श्रेणियों के लिए वर्ष 1992 के कोटा स्तर का पूरा उपयोग कर लिया था तथा अमरीका में और आयात करने की यदि उसे अनुमति दी जाती है तो उससे अत्यधिक लदान करना पड़ेगा। इस प्रतिबन्ध के कारण कुछ निर्यातक अपने वैध कोटाओं का उपयोग नहीं कर सके। तथापि, ऐसे निर्यातकों को हुए घाटों के बारे में सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

Proposals of Restarting Closed Textile Mill Under Co-operatives

2047. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have received proposals from Labour Organisation to restart closed Textile Mills under the co-operative sector;

(b) if so, what is the number of such proposals received from the State of Maharashtra; and

(c) whether Government have taken any decision in this regard?